एकीकृत रिपोर्ट

एकीकृत रिपोर्ट, बाह्य परिवेश, जिससे अल्पावधि, मध्यम–अवधि और दीर्घावधि में मूल्य सृजन होता है, के संदर्भ में किसी संगठन की कार्यनीति, सुशासन, प्रदर्शन और अपेक्षाओं के संबंध में एक संक्षिप्त संचार है। यह किसी संगठन द्वारा प्रयुक्त संसाधनों और संबंधों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और इसमें किसी संगठन द्वारा समय के साथ मूल्यों के सृजन के तरीकों की व्याख्या भी करती है। एकीकृत रिपोर्ट, वित्तीय पूंजी से परे किसी एंटिटी द्वारा सृजित मूल्य के समग्र दृष्टिकोण को उजागर करते हुए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणाली में योगदान करके पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करती है।

आरईसी ने कारोबारों में दीर्घकालिक निर्णय लेने और योजना बनाने में मार्गदर्शन करने वाली छह पूंजियों के माध्यम से कारोबार प्रकटनों पर निर्भर करते हुए, स्वेच्छा से, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल (आईआईआरसी) के फ्रेमवर्क के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है।

आरईसी के सुशासन ढांचे के संबंध में, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अपेक्षा – जिसका स्पष्टीकरण निगमित सुशासन के संबंध में रिपोर्ट में दिया गया है – को छोड़कर, लागू कानूनों और विनियमों की सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विभिन्न निर्देशों का भी पालन करती है। निगमित सुशासन के संबंध में आरईसी के आंतरिक दिशानिर्देशों, जो इसके सुशासन दृष्टिकोण और ढांचे को संहिताबद्ध करते हैं, को http://www.recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf पर देखा जा सकता है।

आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें टर्नओवर, निवल लाभ, निवल मूल्य और ईपीएस के मापदंडों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:

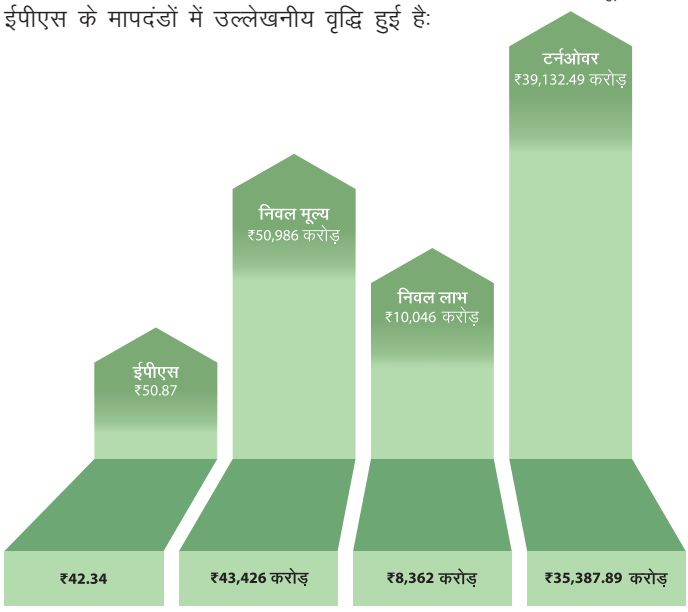

कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसे विद्युत क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरईसी की वित्तीय गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा और साथ ही ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित विद्युत क्षेत्र की सम्पूर्ण गतिविधियों को शामिल किया जाता हैं। आरईसी राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी, परियोजना कार्यान्वयन/प्रबंधन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। आरईसी आधी से अधिक शताब्दी से कार्यशील है।

आरईसी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक सरकारी कंपनी है। मार्च 2019 से, कंपनी की अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में ही एक अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के पास है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी समझौता–ज्ञापन दिशानिर्देशों में निर्धारित ढांचे के तहत आरईसी ने अपनी धारक कंपनी, पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया। समझौता–ज्ञापन में कंपनी के लिए प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों को रेखांकित किया गया है, जिन्हें विद्युत मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, आरईसी के एमओयू स्कोर को 100 में से 100 के स्कोर के साथ ''उत्कृष्ट'' का दर्जा दिया गया था। आरईसी, उक्त वर्ष में यह उपलब्धि हासिल करने वाला एकमात्र सीपीएसई था।

आरईसी आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में स्थापित होने की आशा रखता है। आरईसी, अपने हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के लिए, गैर–विद्युत अवसंरचना और वितरण कार्यों के वित्तपोषण के क्षेत्र में भी कार्य करके अपने कारोबार में विविधता लाने पर विचार कर रहा है। यह छह पूंजियों अर्थात् वित्तीय पूंजी, विनिर्मित पूंजी, बौद्धिक पूंजी, सामाजिक और संबंध पूंजी, मानव पूंजी और प्राकृतिक पूंजी में निवेश के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

वित्तीय पूंजी

आरईसी के संबंध में, अपनी सेवाओं अर्थात् विद्युत क्षेत्र को ऋण की व्यवस्था में उपयोग के लिए उपलब्ध निधियों को वित्तीय पूंजी कहा जाता है। आरईसी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नवीकरणीय के साथ–साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के लिए विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित सभी गतिविधियों के लिए एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।

आरईसी को क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए से अपने घरेलू ऋण लिखतों के लिए "एएए" रेटिंग तथा मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" रेटिंग, जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के बराबर है, प्राप्त हुई है।

31 मार्च, 2022 तक, कंपनी के पास कंपनी के कुल संसाधन और उनकी तैनाती ₹410,412.61 करोड़ थी, जिसका विवरण इस प्रकार था:

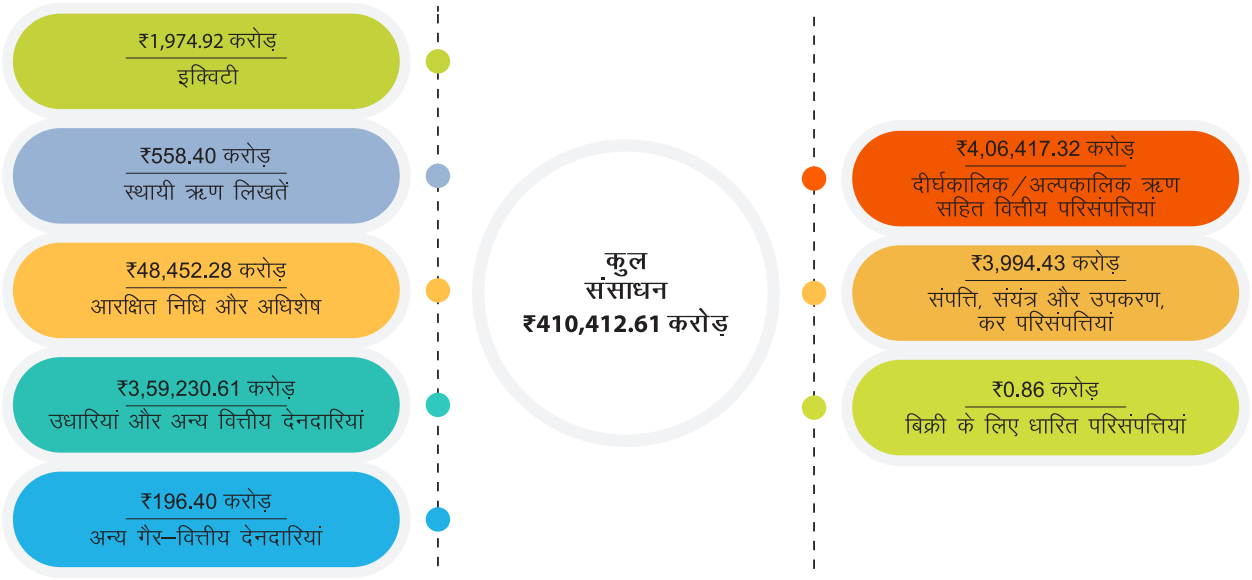

कंपनी के कारोबार की प्रकृति को देखते हुए, उधार राशियां, निधियों के स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी की उधारियों में संस्थागत बॉण्ड, विदेशी मुद्रा उधार, एफसीएनआर (बी) ऋण, पूंजीगत लाभ बॉण्ड, कर मुक्त बॉण्ड, इंफ्रा बॉण्ड, वाणिज्यिक पेपर और बैंकों और वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय एजेंसियों से लिए गए ऋण शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाना, वित्तपोषण कारोबार में लाभप्रदता का आधार है। आरईसी लगातार प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाता रहा है। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, बकाया उधारियों के लिए कुल भारित औसत वार्षिक लागत 7.00% (पिछले वर्ष के लिए 7.26% से कम) रही।

कंपनी द्वारा इन संसाधनों का परिनियोजन मुख्य रूप से विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत ऋण के रूप में की जाती है। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आरईसी के ऋण पोर्टफोलियो को उत्पादन परियोजनाओं में 39%, पारेषण परियोजनाओं में 17%, वितरण परियोजनाओं में 40%, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 3% और अल्पकालिक ऋणों में 1% के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, आरईसी के ऋण पोर्टफोलियो का 86% राज्य क्षेत्र की योजना/परियोजनाएं हैं, इसके बाद निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में 9% और संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं में 5% हैं। आरईसी की गैर–प्रदर्शित परिसंपत्तियां (एनपीए) इस उद्योग में कार्यशील अन्य संस्थाओं में सबसे कम में से एक हैं।

अपनी वित्तीय पूंजी के माध्यम से, आरईसी न केवल अपने शेयरधारकों और निवेशकों के लिए, बल्कि देश में पूरे विद्युत क्षेत्र के लिए मूल्य बनाने में सक्षम है। आरईसी ने अपनी लाभप्रदता बनाए रखी है और अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है।

विनिर्मित पूंजी

एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है। हालाँकि, कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी है और 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, विभिन्न उत्पादन, पारेषण और वितरण योजनाओं के लिए ₹7,54,260 करोड़ की संचयी राशि का वितरण किया है। औद्योगिक गतिविधि, सेवा क्षेत्र के साथ–साथ आम आदमी के दिन–प्रतिदिन के जीवन में विद्युत एक महत्वपूर्ण इनपुट है और आरईसी का योगदान देश भर में विद्युत अवसंरचना के उल्लेखनीय निर्माण पर केंद्रित होता है।

अपनी प्रकृति के कारण, आरईसी द्वारा परिसंपत्तियों का उपयोग आईटी और संचार अवसंरचना और कार्यालय की आपूर्ति तक सीमित है। यह उल्लेख करना उचित है कि सभी भौतिक आवश्यकताओं को कंपनी में निर्धारित खरीद दिशानिर्देशों, जिसमें जीईएम (गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस) पोर्टल भी शामिल है, के अनुसार पूरा किया जाता है।

कंपनी नवीनतम विशेषताओं वाले ई–बिजनेस ईआरपी का उपयोग करती है। ईआरपी हार्डवेयर को आरईसी डाटा सेंटर के निजी क्लाउड परिवेश में स्थानांतरित किया गया है। कंपनी ने नेटवर्क, बैंडविड्थ और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क में सुधार किया है। निर्बाध संचालन के लिए, सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क, महत्वपूर्ण व्यावसायिक एप्लीकेशनों तक दूरवर्ती स्थान से पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। आरईसी का प्राथमिक डाटा केंद्र और डिजास्टर रिकवरी सेंटर आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित है और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन करता है। आरईसी, आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के लिए निर्धारित आईटी सुरक्षा निर्देशों का भी कार्यान्यन करता है। कंपनी विद्युत क्षेत्र में कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में 'ई–ऑफिस' प्रणाली, जो कागज रहित कामकाज की सुविधा प्रदान करती है, को अपनाने वाली शुरूआती संस्थाओं में से एक थी।

बौद्धिक पूंजी

कंपनी ने दावों की प्रोसेसिंग के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों में आईएसओ 9001:2015 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है। कंपनी ने बेहतर ई–गवर्नेंस प्राप्त करने की दिशा में अपनी आईटी पहल के हिस्से के रूप में, आंतरिक रूप से विकसित बहुत–सी प्रणालियों को भी परिनियोजित किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कॉर्पोरेट नेटवर्क के बाहर गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने से रोकने के लिए डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर में डाटा लीकेज एंड प्रिवेंशन (डीएलपी) सिस्टम लागू किया है।

आरईसी का वर्ष 1979 से एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी विद्युत प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग – आरईसीआईपीएमटी) भी है, जो तकनीकी और गैर–तकनीकी क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र के मानव संसाधनों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। आरईसीआईपीएमटी को विद्युत मंत्रालय और विभिन्न विद्युत क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नियोजित किया गया है। यह संस्थान, विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) स्कीम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित कर रहा है।

यह उल्लेख करना उचित है कि महामारी के दौरान भी, आरईसीआईपीएमटी द्वारा समान गति से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। व्यक्तिगत रूप से आयोजित प्रशिक्षण के साथ ऑनलाइन सत्र और वेबिनार की मदद से, आरईसीआईपीएमटी, वित्तीय वर्ष 2021–22 में 20,728 कार्मिकों के लिए 64,361 प्रशिक्षण कार्य–दिवस की उपलब्धित हासिल करने में सक्षम रहा है।

मानव पूंजी

आरईसी के पास अनुकूल संस्कृति और सहायक परिवेश के साथ पेशेवर रूप से योग्य, अनुभवी और कुशल कार्यबल है, जो न केवल इसकी मानव पूंजी को प्रेरित करता है बल्कि इसे कंपनी के साथ बनाए रखने में मदद करता है। मानव संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंपनी में एक मजबूत प्रणाली है। मानव संसाधन को शुरू से ही संगठन के मिशन और नीतिगत ढांचे के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है। कार्य के दौरान भी, विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल और कारोबारिक कुशाग्रता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

आरईसी के मानव संसाधन का भंडार, विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधित्व के साथ विविधरूपी है। आरईसी विभिन्न पहलों और नीतियों के माध्यम से अपनी महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाता है; और एक लाभकारी कार्य परिवेश, जो इसे अपने कर्मचारियों को पेशेवरों और विशिष्ट–व्यक्तियों के रूप में विकसित होने के लिए अनुकूल बनाता है, को बढ़ावा देते हुए, लैंगिक समानता की दिशा में प्रयास करता है।

कल्याण–उन्मुख नीतियों के माध्यम से कार्य जीवन संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, निवारक स्वास्थ्य मुद्दों पर समय–समय पर वार्ता आयोजित की जाती है। कंपनी के कर्मचारियों के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक सुसज्जित व्यायामशाला है। कर्मचारी विभिन्न खेलों, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं, जो उनके समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं।

सामाजिक और संबंध पूंजी

आरईसी न केवल एक वित्तीय संस्थान है, बल्कि समग्र रूप से पूरे देश में, सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत संगठन है। विभिन्न विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी होने के नाते, कंपनी ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित समय–सीमा के भीतर देश के सभी गैर–विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा, कंपनी ने सरकार के सामूहिक विकास के एजेंडे में योगदान करते हुए, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत देश में लगभग 3 करोड़ घरों के विद्युतीकरण को सुकर बनाया है।

आरईसी, अपनी सीएसआर शाखा – सीएसआर फाउंडेशन – के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्यों का भी समर्थन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं, जिनमें पीएम केयर्स फंड और सीएसआर खर्च के लिए ₹50 करोड़ का अंशदान, विभिन्न आकांक्षी जिलों का विकास, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता का वितरण, कैंसर स्क्रीनिंग और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, अल्पसुविधाप्राप्त छात्रों के लिए अध्ययन और बुनियादी आवश्यकताओं का समर्थन करना और कोविड–19 के संबंध में विभिन्न स्थानों पर ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों के लिए सहायता शामिल है, के लिए ₹171.07 करोड़ (पिछले वर्ष से ₹3.45 करोड़ के अतिरिक्त खर्च सहित) की राशि खर्च की। इसके अतिरिक्त, आरईसी पूरे भारत में महिला हॉकी, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग पर जोर देते हुए खेल सुविधाओं के विकास का भी समर्थन करता है।

प्राकृतिक पूंजी

आरईसी हमेशा प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करके और इनकी बर्बादी को कम करके पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करता है।

विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण संगठन के रूप में, आरईसी अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में लगातार सुधार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने 1,609 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता के साथ 15 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल ₹14,733.52 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए। अब तक, आरईसी ने देश के लिए हरित भविष्य का समर्थन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के तहत लगभग 11.6 गीगावाट क्षमता के लिए वित्तपोषण किया है।

आरईसी ने, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लागू आरईसी और केएफडब्ल्यू के बीच आधिकारिक विकास सहायता – केएफडब्ल्यू– III एलओए के तहत, वर्ष 2016 में पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (ईएसआईए) रिपोर्ट तैयार की थी। ईएसआईए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने के लिए आरईसी के रोडमैप के रूप में कार्य करता है।

आरईसी ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, जैसे कि फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी), जो हानिकारक उत्सर्जन और सूक्ष्म कणों की रोकथाम में मदद करते हैं, की स्थापना के लिए भी वित्तपोषण कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना के लिए 9 ऐसी परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है, जिनकी कुल ऋण राशि ₹752 करोड़ है।

आरईसी ने अपनी विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय भवन पर 979 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) रूफटॉप सोलर प्लांट संस्थापित किया है। जुलाई 2021 में कार्यशील इस प्लांट ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में 8.22 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन किया है, जिससे भवन की कुल लोड आवश्यकता के लगभग 50% पूर्ति हुई। भवन में ऊर्जा की बचत करने वाली विशेषताएं जैसे कि एयर कंडीशनिंग के लिए विद्युत की खपत को 30% तक कम करने के लिए स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), स्वचालित सेंसर नियंत्रित प्रकाश और मोटराइज्ड ब्लाइंड से युक्त बॉयो–क्लाइमेट ग्लास से बना अग्रभाग भी हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 20 अगस्त, 2022